फुलिया टुडू और अन्य
बनाम
बिहार राज्य (अब झारखंड)
14 सितंबर, 2007
(डॉ अरिजीत पसायत और डी. के जैन, न्यायमूर्तिगण)

दंड संहिता, 1860-धारा 304 (भाग I) सह पठित धारा 34-हत्या के लिए अभियोजन-मृतक पर लाठी से हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई-धारा 302 सह पठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा- औचित्य-अभिनिर्धारित तथ्यों पर, एक प्रहार एक छोटी छड़ी से किया गया था, और जिस स्थान पर हमला हुआ था, उस स्थान पर मंद रोशनी की गई थी-मामले के तथ्यों और धारा 299 और 300 में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के आलोक में दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग I) सह पठितधारा 34 के तहत दोषसिद्धि को बदल दिया गया और दस साल की अभिरक्षा की सजा दी गई।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अपीलार्थी बीएम के खिलाफ शिकायत का पोषण कर रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, अपीलकर्ताओं ने बीएम का पीछा किया और बीएम ने बीएस के घर में शरण ली। अपीलार्थी-प्रथम अभियुक्त ने बीएम पर लाठी से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। जब बीएस ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच पड़ताल की गई। निचली अदालत ने अपीलार्थियों को धारा 302 सह पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की। यह तर्क दिया कि दूसरे अभियुक्त ने मृतक का हाथ पकड़ रखा था जबकि पहले अभियुक्त ने केवल एक लाठी प्रहार किया था जिससे घातक चोट नहीं लग सकती थी, इस प्रकार धारा 302 लागू नहीं होती है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित 1.1 दंड सहिंता की योजना में, गैर-इरादतन हत्या जाति है और 'हत्या' इसकी प्रजाति है। सभी 'हत्या' 'गैर-इरादतन हत्या' है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर,

'गैर इरादतन हत्या' बिना 'हत्या की विशेष विशेषताओं' के गैर इरादतन हत्या है जो हत्या के बराबर नहीं है '। सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में सजा तय करने के उद्देश्य से, आईपीसी व्यावहारिक रूप से गैर-इरादतन हत्या के तीन स्तरों को मान्यता देता है। पहला है,. 1, 'प्रथम श्रेणी की गैर इरादतन हत्या'। यह गैर इरादतन हत्या का सबसे गंभीर रूप है, जिसे धारा 300 में 'हत्या' के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा 'दूसरे दर्जे की गैर-इरादतन हत्या' है। यह धारा 304 के पहले भाग के तहत दंडनीय है। फिर गैर इरादतन हत्या तीसरी श्रेणी' है। यह सबसे कम प्रकार की गैर-इरादतन हत्या है और इसके लिए प्रदान की गई सजा भी तीन श्रेणियों के लिए प्रदान की गई सजाओं में सबसे कम है। यह धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है। [अनुच्छेद 7) (1001-च, छ; 1002-क]

1.2. धारा 299 का कारण (ख) धारा 300 के खंड (2) और (3) से मेल खाता है। खंड (2) के अधीन अपेक्षित दोषी मन की विभेदक विशेषता अपराधी के पास उस विशेष पीड़ित के ऐसी विचित्र दशा या स्वास्थ्य की स्थिति में होने के संबंध में ज्ञान है कि उसे होने वाली आंतरिक हानि घातक होने की संभावना है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी हानि प्रकृति के सामान्य तरीके से किसी व्यक्ति की मृत्यु स्वास्थ्य या स्थिति का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। 'मृत्यु का कारण बनने का इरादा' खंड की एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है (2). हत्या को इस खंड के दायरे में लाने के लिए केवल शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे के साथ-साथ अपराधी के उस चोट की संभावना के बारे में ज्ञान होना पर्याप्त है जिससे विशेष रूप से पीड़ित की मृत्यु हो सकती है। खंड (2) के इस पहलू को धारा 300 में संलग्न चित्रण (ख) द्वारा व्यक्त किया गया है। (अनुच्छेद 9) (1003-क-ग)

1.3. धारा 299 का खंड (ख) अपराधी की ओर से अभिधारणा ऐसा ज्ञान नहीं करता है। धारा 300 के खंड (2) के तहत आने वाले मामलों के उदाहरण हो सकते हैं जहां हमलावर जानबूझकर एक मुट्ठी के झटके से मौत का कारण बनता है, यह जानते हुए कि पीड़ित एक बढ़े हुए यकृत, बढ़े हुए प्लीहा या रोगग्रस्त दिल से पीड़ित है और इस तरह के झटके. यकृत के टूटने के कारण,के रूप में उस विशेष व्यक्ति की मौत का कारण बनने की संभावना है; या प्लीहा या दिल की विफलता, जैसा कि मामला हो सकता है। पीड़ित की बीमारी या विशेष कमजोरी के बारे में हमलावर को ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, न ही मृत्यु या शारीरिक चोट का कारण बनने का इरादाः मृत्यु का कारण बनने के लिए सामान्य प्रकृति में अपराध हत्या नहीं होगा, भले ही चोट के कारण मृत्यु, जानबूझकर दी गई थी। धारा 300 के खंड (3) में, धारा

299 के संगत खंड (ख) में आने वाले 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना' शब्दों के स्थान पर, 'प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में पर्याप्त' शब्दों का उपयोग किया गया है। जाहिर है, अंतर एक शारीरिक चोट के बीच है जो मृत्यु का कारण बन सकती है और एक शारीरिक चोट जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकती है। भेद ठीक है लेकिन वास्तविक है और अगर अनदेखी, न्याय के गर्भपात में । धारा 299 के खंड (ख) और धारा 300 के खंड (3) के बीच का अंतर इच्छित शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु की संभावना की श्रेणी में से एक है। अधिक व्यापक रूप से, यह मृत्यु की संभावना की श्रेणी है जो यह निर्धारित करती है कि क्या एक गैर-इरादतन हत्या गंभीर, मध्यम या निम्नतम श्रेणी की है।धारा 299 के खंड (ख) में 'संभावित' शब्द संभावित की भावना को व्यक्त करता है जो केवल संभावना से अलग है। शब्द हैं "शारीरिक चोट..... प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है" इसका मतलब है कि प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मृत्यु चोट का "सबसे संभावित" परिणाम होगा। (अनुच्छेद 10) (1003-घ-छ; 1004-क)

1.4. खंड (3) के भीतर आने वाले मामलों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा मृत्यु का कारण बनना हो, जब तक कि मृत्यु जानबूझकर शारीरिक चोट या सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोटों से होती है। (अनुच्छेद 11) (1004-क-ख)

राजवंत और अन्य बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 1874, इस मामले पर पर भरोसा किया।

1.5. विरसा सिंह मामले द्वारा खंड 'तृतीय' की प्रयोज्यता के लिए निर्धारित परीक्षण अब भारतीय कानूनी प्रणाली में अंतर्निहित है और कानून के नियम का हिस्सा सी बन गया है। धारा 300 आईपीसी के खंड III के तहत, गैर इरादतन हत्या है, अगर दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रहे हैं: जो(क) वह कार्य जो मृत्यु का कारण बनता है, मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया है या शारीरिक क्षति करने के इरादे से किया गया है; और (ख) जो चोट पहुँचाने का इरादा है वह प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुंचाने का एक इरादा था, जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में, मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त

था, अर्थात्, जो चोट मौजूद पाई गई थी वह वह चोट थी जिसे देने का इरादा था। (अनुच्छेद 15) (1005-ड, च, छ]

विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1958) एस. सी. 465 पर भरोसा किया गया।

1.6. धारा 299 का खंड (ग) और धारा 300 का खंड (4) दोनों मृत्यु का कारण बनने वाले कार्य की संभाव्यता के ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। धारा 300 का खंड (4) वहां लागू होगा जहां अपराधी का किसी व्यक्ति या सामान्य रूप से व्यक्तियों की मृत्यु की संभावना के बारे में ज्ञान, जैसा कि किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों से अलग है, जो उसके आसन्न खतरनाक करक के कारण हुआ है, एक व्यावहारिक निश्चितता के लिए अनुमानित है। अपराधी की ओर से ऐसा ज्ञान उच्चतम संभावना का होना चाहिए, यह कार्य अपराधी द्वारा मृत्यु या ऐसी चोट पहुंचाने के जोखिम के लिए किसी भी बहाने के बिना किया गया है। [अनुच्छेद 171 (1006-क, ख, ग]

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या और अन्य, (1976) 4, एस. सी. सी. 382; अब्दुल वाहिद खान @वाहिद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जेटी (2002) 6 एससी 274 और ऑगस्टीन सल्दान्हा बनाम कर्नाटक राज्य, (2003 से धारा 472 तक, निर्दिष्ट।

2. कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यात्मक स्थिति की जांच की जानी चाहिए।यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि जब भी एक झटका दिया जाता है तो आईपीसी की धारा 302 को खारिज कर दिया जाता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। उपयोग किया गया हथियार, हथियार का आकार, वह स्थान जहाँ हमला हुआ था, हमले की पृष्ठभूमि के तथ्य, शरीर का वह हिस्सा जहाँ प्रहार किया गया था, कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में माना जाता है कि एक छोटी छड़ी के साथ एक झटका दिया गया था, और जिस स्थान पर हमला किया गया था वह तुरंत जलाया गया था मामला धारा 304भाग 1 द्वारा कवर किया गया है न कि धारा 302 द्वारा। इसलिए, प्रत्येक अपीलार्थी को धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग I के तहत दोषी ठहराया जाता है, न कि आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत। दस साल की अभिरक्षा की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।(अनुच्छेद 20 और 21) ([1006-ड,च,छ)

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 1221/2007।

रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश आपराधिक अपील संख्या 130/1989 दिनांक 07/02/2006 को।

अपीलार्थियों की ओर से डी. अरूप बनर्जी और अपर्णा झा।

प्रतिवादी के लिए मनीष कुमार शरण।

न्यायालय का निर्णय. डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति द्वारा।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसमें अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 34 के साथ पठित आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं: बिटिया सोरेन (अभियोजन साक्षी - 8) बिटी मुर्मू की भाभी है (यहाँ 'मृतक' के रूप में संदर्भित किया गया है)। पहले अपीलार्थी का पुत्र बीमार पड़ गया और अपीलार्थी/अभियुक्त इस धारणा में थे कि चूंकि मृतक, बिटी मुर्मू एक चुड़ैल है, इसलिए उसने अभियुक्त के पुत्र पर जादू किया है और इसलिए, वे मृतक के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। घटना के दिन, जब ग्रामीण एक ग्रामीण, झोरा हंसदा, के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट गए थे। अपीलार्थी फुलिया टुडू और मालगो सोरेन ने मृतक, बिटी मुर्मू का पीछा किया और उसने बिटिया सोरेन (अभियोजन साक्षी -8) के घर में शरण ली अपीलकर्ताओं ने घर में प्रवेश किया और मृतक, बिटी मुर्मू को पकड़ लिया। उस समय बिटिया सोरेन (अभियोजन साक्षी - 8) धान की कटाई में लगी हुई थी। पहले आरोपी ने मृतक का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला और मृतक नीचे गिर गया। पहले आरोपी फुलिया टुडू ने उस पर लाठी से हमला किया और जब अभियोजन साक्षी - 8 ने हस्तक्षेप) करने का प्रयास किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अन्य आरोपी उस समय वहां मौजूद थे और घटना के बाद, वे वहां से भाग गए। अभियोजन साक्षी - 8 के पति सहित ग्रामीणों के लौटने के बाद, उन्हें सूचना दी गई। इसके बाद, अभियोजन साक्षी - 8 द्वारा अपराहन 2.30 बजे पर रानेश्वर पुलिस स्टेशन में फर्द बयान प्रदर्श 3 दिया गया, जो एक अपराध के रूप में दर्ज किया गया था और प्रदर्श 5 पहली

सूचना रिपोर्ट है और बिजेंद्र नारायण सिंह द्वारा जांच की गई थी। अभियोजन साक्षी - 9, जांच करने पर, घटना स्थल पर पहुंचा, जांच रिपोर्ट, तैयार की, और शव परीक्षण करने के लिए डॉक्टर की मांग के साथ शव को अस्पताल भेज दिया। जाँच पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। जैसे ही अभियुक्त व्यक्तियों ने बेगुनाही का अनुरोध किया, मुकदमा चलाया गया।

4. निचली अदालत ने अभियोजन साक्षी - 8 के साक्ष्य पर विश्वास किया और आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 302 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की और प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, आरोपी किस्टो किस्कु को बरी कर दिया गया।

5. इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उठाया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि केवल आरोप यह था कि अभियुक्त 2 ने मृतक के हाथ पकड़े थे जबकि अभियुक्त 1 ने लाठी चलाई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त 1 द्वारा दिए गए लाठी प्रहार से घातक चोटें नहीं लग सकती थीं। किसी भी स्थिति में, केवल एक झटका दिया गया था और इसलिए, धारा 302 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

6. दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया, जिसने जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके समक्ष दायर अपील को खारिज कर दिया।

7. महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कौन सा उचित प्रावधान लागू किया जाना था। आई. पी. सी. की योजना में गैर-इरादतन हत्या जाति है और 'हत्या' इसकी प्रजाति है। सभी 'हत्या' 'गैर-इरादतन हत्या' है, लेकिन इसके विपरीत नहीं। आम तौर पर, 'गैर इरादतन हत्या' बिना 'हत्या की विशेष विशेषताओं' के गैर इरादतन हत्या है जो हत्या के बराबर नहीं है '। सजा तय करने के उद्देश्य से, सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में, आईपीसी व्यावहारिक रूप से गैर-इरादतन हत्या के तीन स्तरों को मान्यता देता है। पहला है, जिसे कहा जा सकता है, 'प्रथम श्रेणी की गैर इरादतन हत्या'। यह गैर इरादतन हत्या का सबसे गंभीर मामला है, जिसे धारा 300 में 'हत्या' के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे को 'दूसरे दर्जे की गैर इरादतन हत्या' कहा जा सकता है। यह दंडनीय है धारा 304 के प्रथम भाग के अधीन। फिर, 'तीसरी श्रेणी की गैर-इरादतन हत्या' होती है। यह सबसे कम प्रकार की गैर-इरादतन हत्या है

और इसके लिए प्रदान की गई सजा भी तीन श्रेणियों के लिए प्रदान की गई सजाओं में सबसे कम है। इस स्तर की निंदनीय हत्या धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।

8. अकादमिक अंतर 'हत्या' और 'गैर इरादतन हत्या' ने हमेशा अदालतों को परेशान किया है। भ्रम पैदा होता है, यदि न्यायालय इन धाराओं में विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के सही दायरे और अर्थ की दृष्टि खो देते हैं, तो वे खुद को सूक्ष्म अमूर्तता में खींचने की अनुमति देते हैं। इन प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए दृष्टिकोण का सबसे सुरक्षित तरीका धारा 299 और 300 के विभिन्न खंडों में उपयोग किए गए मुख्य शब्दों को ध्यान में रखना प्रतीत होता है। निम्नलिखित तुलनात्मक तालिका दोनों अपराधों के बीच अंतर के बिंदुओं को समझने में सहायक होगी।

धारा 299

एक व्यक्ति गैर इरादतन हत्या करता है यदि वह कार्य किया जाता है जिससे मृत्यु हुई है-

इरादा

(क) मृत्यु का कारण बनने के इरादे से; या (ख) ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से जिससे मृत्यु होने की संभावना है; या

ज्ञान

(ग) इस ज्ञान के साथ कि इस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।

धारा 300

कुछ अपवादों के अधीन गैर इरादतन हत्या है यदि वह कार्य किया जाता है जिसके द्वारा मृत्यु हुई है -

इरादा

(1) मृत्यु का कारण बनने के इरादे से या

(2) ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनने के इरादे से। अपराधी उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने की संभावना जानता है जिसे नुकसान पहुंचाया गया है; या

(3) किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से और शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है; या

ज्ञान

(4) इस ज्ञान के साथ कि कार्य इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि यह सभी संभावनाओं में मृत्यु या इस तरह के कारण होना चाहिए शारीरिक चोट जिसके कारण मृत्यु होने की संभावना है और बिना किसी बहाने के या मृत्यु या ऐसी चोट के जोखिम के बिना जैसा ऊपर किया गया है।

9. धारा 299 का खंड (ख) धारा 300 के खंड (2) और (3) से मेल खाता है। खंड (2) के अधीन अपेक्षित दोषी मन की विभेदक विशेषता यह है कि अपराधी के पास पीड़ित की ऐसी विचित्र स्थिति या स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में ज्ञान है कि उसके कारण होने वाला आंतरिक हानिघातक होने की संभावना है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा हानि प्रकृति के सामान्य तरीके से गैर-स्वास्थ्य या स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं होगा। यह उल्लेखनीय है कि 'मृत्यु का कारण बनने का इरादा' खंड की एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है (2). हत्या को इस खंड के दायरे में लाने के लिए केवल शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा और अपराधी के ज्ञान के साथ ऐसी चोट की संभावना के बारे में जानकारी ही पर्याप्त है जिससे विशेष रूप से पीड़ित की मृत्यु हो सकती है। खंड (2) के इस पहलू को धारा 300 में संलग्न चित्रण (ख) द्वारा व्यक्त किया गया है।

10. धारा 299 का खंड (ख) अपराधी की ओर से ऐसी किसी भी जानकारी को स्वीकार नहीं करता है। धारा 300 के खंड (2) के तहत आने वाले मामलों के उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जहां हमलावर जान-बूझकर एक मुट्ठी के प्रहार से मृत्यु का कारण बनता है, यह जानते हुए कि पीड़ित एक बढ़े हुए यकृत, या बढ़े हुए प्लीहा या रोगग्रस्त हृदय से पीड़ित है और इस तरह के प्रहार से यकृत के टूटने, या प्लीहा या हृदय की विफलता के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, जैसा भी मामला हो। यदि हमलावर को पीड़ित की बीमारी या विशेष कमजोरी के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, और न ही मृत्यु या

शारीरिक चोट का कारण बनने का इरादा था, जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था, तो अपराध हत्या नहीं होगा, भले ही वह चोट जो मौत का कारण बनी, जान बूझकर दी गई थी। धारा 300 के खंड (3) में, धारा 299 के संगत खंड (ख) में आने वाले 'मृत्यु का कारण बनने की संभावना' शब्दों के स्थान पर, "प्रकृति के सामान्य प्रकृति में पर्याप्त" शब्दों का उपयोग किया गया है। जाहिर है, अंतर एक शारीरिक चोट के बीच है जो मृत्यु का कारण बन सकती है और एक शारीरिक चोट जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बन सकती है। भेद ठीक है लेकिन वास्तविक है और यदि इसकी अनदेखी की जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हो सकती है। धारा 299 के खंड (ख) और धारा 300 के खंड (3) के बीच जी अंतर इच्छित शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु की संभावना की श्रेणी में से एक है। इसे अधिक व्यापक रूप से रखने के लिए, यह मृत्यु की संभावना की श्रेणी है जो यह निर्धारित करती है कि क्या एक गैर-इरादतन हत्या गंभीर, मध्यम या गंभीर है। धारा 299 के खंड (ख) में 'संभावना' शब्द संभावित की भावना को व्यक्त करता है जो केवल संभावना से अलग है। "प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक चोट" शब्दों का अर्थ है कि प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मृत्यु चोट का "सबसे संभावित" परिणाम होगा।

11. खंड (3) के भीतर आने वाले मामलों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा मृत्यु का कारण बनना हो, जब तक कि मृत्यु जान बूझकर शारीरिक चोट या चोटों से होती है जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनती है। राजवंत और अन्य बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 1874, इस मामले पर पर भरोसा किया।इस बिंदु का एक उपयुक्त उदाहरण है।

12. विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1958) एस. सी. 465 में न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति विवियन बोस ने खंड (3) के अर्थ और दायरे की व्याख्या की। यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा, "तीसरा" सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्ष रूप से स्थापित करना चाहिए, कि एक शारीरिक चोट मौजूद है; दूसरा चोट की प्रकृति को साबित किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ जांच हैं। तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष चोट को लागू करने का इरादा था; अर्थात, यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था या किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था। एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद

साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ती है, और चौथा यह साबित किया जाना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी वर्णित प्रकार की चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। जाँच का यह भाग विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ और अनुमानित है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है।

13. आई. पी. सी. की धारा 300 के खंड "तृतीय" के अवयवों को प्रसिद्ध न्यायाधीश द्वारा अपनी संक्षिप्त भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया थाः

"जल्द ही कहने के लिए, अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा", “तीसरा”।

सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्ष रूप से स्थापित करना चाहिए कि एक शारीरिक चोट मौजूद है।

दूसरा, चोट की प्रकृति को साबित किया जाना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से जी वस्तुनिष्ठ जांच हैं।

तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुंचाने का इरादा था, अर्थात यह कहना कि यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था, या कि किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था। एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ती है और,

चौथा, यह साबित किया जाना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी प्रकार की चोट प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। जांच का यह हिस्सा विशुद्ध रूप से उद्देश्यपूर्ण और अनुमानित है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है।

14. विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित शब्दों में तीसरे घटक की व्याख्या की (पृष्ठ 468 पर):

"सवाल यह नहीं है कि क्या कैदी का इरादा गंभीर चोट पहुँचाना था या मामूली चोट पहुँचाना था, बल्कि यह है कि क्या वह उस चोट को पहुँचाना चाहता था जो मौजूद साबित हुई है। यदि वह दिखा सकता है कि उसने ऐसा नहीं किया, या यदि परिस्थितियों की समग्रता इस तरह के निष्कर्ष को उचित ठहराती है, तो निश्चित रूप से, धारा के लिए आवश्यक आशय साबित नहीं होता है। लेकिन यदि चोट और इस तथ्य से परे कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने इसे दिया है, तो एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि वह इसे देने का इरादा रखता था। चाहे वह इसकी गंभीरता के बारे में जानता था या गंभीर परिणामों का इरादा रखता था, न तो यहाँ है और न ही वहाँ। जहां तक इरादे का संबंध है, सवाल यह नहीं है कि क्या वह मारने का इरादा रखता था, या किसी विशेष स्तर की गंभीरता से चोट पहुँचाने का इरादा रखता था, बल्कि यह है कि क्या वह प्रश्न में चोट पहुँचाने का इरादा रखता था और एक बार चोट का अस्तित्व साबित हो जाने के बाद इसका कारण बनने का इरादा तब तक माना जाएगा जब तक कि सबूत या परिस्थितियाँ एक विपरीत निष्कर्ष की गारंटी नहीं देती हैं।

15. जे. विवियन बोस के ये अवलोकन *लोकस क्लासिकस* बन गए हैं। विरसा सिंह के मामले (उपर्युक्त) द्वारा खंड "तीसरा" की प्रयोज्यता के लिए निर्धारित परीक्षण अब हमारी कानूनी प्रणाली में निहित है और कानूनी प्रणाली के नियम का हिस्सा बन गया है। धारा 300 आईपीसी के खंड III के तहत, गैर इरादतन हत्या है, अगर दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रहे हैं: जो (क) जो कार्य मृत्यु का कारण बनता है, वह मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया है या शारीरिक क्षति करने के इरादे से किया गया है; और (ख) जो चोट पहुँचाने का इरादा है, वह प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट को पहुँचाने का एक इरादा था, जो प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में, मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था, अर्थात्, जो चोट मौजूद पाई गई थी वह वह चोट थी जिसे जी द्वारा लगाया जाना था।

16. इस प्रकार, विरसा सिंह के मामले में निर्धारित नियम के अनुसार, भले ही अभियुक्त का इरादा प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक चोट पहुंचाने तक सीमित था, और मृत्यु का कारण बनने के इरादे तक विस्तारित नहीं था, अपराध हत्या होगी। चित्रण (ग) इस बिंदु को स्पष्ट रूप से सामने लाता है।

17. धारा 299 का खंड (ग) और धारा 300 का खंड (4) दोनों मृत्यु का कारण बनने वाले कार्य की संभाव्यता की जानकारी की अपेक्षा करते हैं। इस मामले के उद्देश्य के लिए इन

संबंधित खंडों के बीच अंतर पर अधिक विस्तार करना आवश्यक नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि धारा ख 300 का खंड (4) वहां लागू होगा जहां अपराधी का किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु की संभावना के बारे में ज्ञान, जैसा कि किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों से अलग है, जो उसके आसन्न खतरनाक कार्य के कारण हुआ है, एक व्यावहारिक निश्चितता का अनुमान लगाता है। अपराधी की ओर से ऐसा ज्ञान उच्चतम संभावना का होना चाहिए, यह कार्य अपराधी द्वारा मृत्यु या ऐसी चोट के जोखिम के लिए किसी भी बहाने के बिना किया गया है जैसा कि ऊपर कहा गया है।

18. उपरोक्त केवल व्यापक दिशानिर्देश हैं और *कास्ट आयरन* अनिवार्यताएं नहीं हैं। अधिकांश मामलों में, उनके पालन से न्यायालय के कार्य में सुविधा होगी। लेकिन कभी-कभी तथ्य इतने आपस में जुड़े होते हैं और दूसरे और तीसरे चरण एक-दूसरे में इतने उलझे हुए होते हैं कि दूसरे और तीसरे चरण में शामिल मामलों को अलग से देखना सुविधाजनक नहीं हो सकता है।

19. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या और अन्य , [1976] 4 एस. सी. सी. 382, अब्दुल वाहिद खान @वाहिद और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जेटी (2002) 6 एससी 274, और ऑगस्टीन सल्दान्हा बनाम कर्नाटक राज्य, [2003] 10 एससीसी 472 में इस न्यायालय द्वारा स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया था।

20. उपर्युक्त कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यात्मक स्थिति की जांच की जानी चाहिए। यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि जब भी एक झटका दिया जाता है तो आईपीसी की धारा 302 को खारिज कर दिया जाता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। उपयोग किया गया हथियार, हथियार का आकार, वह स्थान जहाँ हमला हुआ था, हमले की पृष्ठभूमि के तथ्य, शरीर का वह हिस्सा जहाँ प्रहार किया गया था, कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में माना जाता है कि एक छोटी छड़ी से एक प्रहार किया गया था, और जिस स्थान पर हमला हुआ था, वह मंद रोशनी में था। अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि मामला आईपीसी की धारा 304 भाग I द्वारा कवर किया गया है न की आईपीसी की धारा 302 द्वारा।

21. इसलिए, प्रत्येक अपीलार्थी को धारा 304 भाग 1 सह पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया जाता है न कि धारा 302 सह पठित धारा 34 के साथ। दस साल की अभिरक्षा की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी।

22. अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है।

यह अनुवाद मदन मोहन प्रिय, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।